+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# TODAY'S ANALYSIS
# (आज का विश्लेषण)
## (18 January 2025)

### Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार, लेकिन कौशल में गंभीर अंतर
- पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान क्यों चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर निकल जाए?
- MCQ

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार, लेकिन कौशल में गंभीर अंतर:

## चर्चा में क्यों है?

- QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ग्रीन स्किल्स सहित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारियों के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। लेकिन आर्थिक परिवर्तन के मामले में, भारत को सूचकांक में 40वें स्थान पर और भविष्य की नौकरियों के लिए वांछित कौशल रखने वाले कार्यबल के मामले में 37वें स्थान पर रखा गया है।
- कुल मिलाकर, भारत सभी संकेतकों में 25वें स्थान पर रहा, जिसमें कौशल और नियोक्ता की जरूरतों, शैक्षणिक तत्परता और आर्थिक परिवर्तन के बीच संरेखण भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समग्र रैंकिंग भारत को "भविष्य के कौशल का दावेदार" बनाती है।

## QS सर्वेक्षण ने किन संकेतकों को मापा है?

- QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके यह मूल्यांकन करता है कि देश अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितने सुसज्जित हैं।
- QS (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) वैश्विक उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए दुनिया के अग्रणी डेटा विश्लेषण और समाधान प्रदाताओं में से एक है। इस सर्वेक्षण ने QS द्वारा पहचाने गए चार व्यापक संकेतकों का मूल्यांकन किया:
- **भविष्य की नौकरियां:** यह भविष्य की नौकरियों में आवश्यक कौशल के लिए भर्ती करने के लिए देश की तत्परता का मूल्यांकन करता है।
- **कौशल फिट:** यह मापता है कि देश स्नातकों को नियोक्ताओं की इच्छा के अनुसार कौशल से कितनी अच्छी तरह लैस कर रहे हैं।
- **शैक्षणिक तत्परता:** यह मापता है कि काम के भविष्य के लिए कोई देश कितनी अच्छी तरह तैयार है।
- **आर्थिक परिवर्तन:** यह विभिन्न प्रमुख संकेतकों की जांच करके काम और कौशल के विकास और भविष्य का समर्थन करने के लिए देश की तत्परता का आकलन करने के लिए एक भारित सूत्र का उपयोग करता है।

## इन संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

### 'भविष्य के नौकरियों' संकेतक में भारत दूसरे स्थान पर:

- भारत 'भविष्य के नौकरियों' संकेतक में दूसरे स्थान पर है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है, और जर्मनी और कनाडा जैसे देशों से आगे है।
- यह संकेतक मापता है कि डिजिटल, AI और हरित कौशल की बढ़ती मांग, जो अर्थव्यवस्थाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित और टिकाऊ उद्योगों की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है, को पूरा करने के लिए नौकरी बाजार कितनी अच्छी तरह तैयार है।
- सर्वेक्षण का मूल्यांकन बड़े पैमाने पर मांग पक्ष से किया गया है, यानी नौकरी पोस्टिंग के माध्यम से। यह स्कोर दुनिया भर में 28 करोड़ से अधिक नौकरी पोस्टिंग के विश्लेषण से प्राप्त किया गया है।

### 'कौशल फिट' में टॉप 30 देशों में भारत सबसे निचले पायदान पर:

- 'कौशल फिट' के मामले में भारत का स्कोर 59.1 रहा, जो कुल मिलाकर शीर्ष 30 देशों में सबसे खराब है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत भर के नियोक्ता तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं।

- यह कमी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक चुनौती को रेखांकित करती है, जो नियोक्ताओं की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है।

**'सततता से जुड़े भविष्योन्मुखी नवाचार' उप-मापदंड में प्रदर्शन सबसे खराब:**

- इस विश्लेषण में भारत को 'आर्थिक क्षमता' के मामले में पूरे 100 अंक दिए गए हैं, लेकिन 'सततता से जुड़े भविष्योन्मुखी नवाचार' के पैरामीटर पर उसका प्रदर्शन सबसे खराब है, जो दोनों ही 'आर्थिक परिवर्तन' के बड़े दायरे के अंतर्गत उप-मापदंड हैं।
- सततता से जुड़े भविष्योन्मुखी नवाचार' में भारत को 100 में से केवल 15.6 अंक मिले हैं। इसकी तुलना में G7 देशों को 68.3, यूरोपीय संघ के देशों को 59, एशिया-प्रशांत देशों को 44.7 और अफ्रीकी देशों को 25.4 अंक मिले हैं।

**भारत 'आर्थिक परिवर्तन' पैरामीटर पर 40वें स्थान पर है:**

- भारत ने 'आर्थिक परिवर्तन' पैरामीटर पर 58.3 अंक प्राप्त किए हैं, और 40वें स्थान पर है। भारत का आर्थिक परिवर्तन विकास, श्रमबल दक्षता और उच्च शिक्षा की उभरती भूमिका के परस्पर क्रिया द्वारा संचालित है।

- हालांकि, निवेश और नवाचार क्षमता में अंतर ऐसी चुनौतियां पेश करता है जो दीर्घकालिक विकास को धीमा कर सकती हैं।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, भारत को आर्थिक गति को मजबूत उच्च शिक्षा सुधारों और कौशल विकास के साथ जोड़ना होगा, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी स्थिति सुनिश्चित हो सके।

## 'शैक्षणिक तत्परता' सूचकांक में भारत 26वें स्थान पर:

- 'शैक्षणिक तत्परता' सूचकांक पर भारत का स्कोर 89.9 है, जो देश को इस पैरामीटर के लिए 26वें स्थान पर रखता है।

## भारत की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति के बारे में क्या कहा गया है?

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के स्नातक "आवश्यक प्रासंगिक कौशल में बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं"। भारत का समग्र 'कौशल फिट' स्कोर APAC (एशिया-प्रशांत) के समकक्षों की तुलना में कम है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नियोक्ता तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- यह कमी "भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक चुनौती को रेखांकित करती है"। इसे संबोधित करने के लिए, "विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में रचनात्मकता, समस्या समाधान और उद्यमशीलता की सोच को शामिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और शिक्षा को श्रमबल की मांगों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए उद्योग के साथ मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए"।
- सरकारी नीति और उच्च शिक्षा नीति को "निरंतर और आजीवन पुनः कौशल कार्यक्रमों में श्रमिकों को फिर से शामिल करने के लिए एक केंद्रित रणनीति की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुशल श्रमिक प्रासंगिक और उत्पादकता में योगदानकर्ता बने रहें"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

# पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान द्वारा भारत को WTO से बाहर निकलने की मांग का मुद्दा:

## चर्चा में क्यों है?

- पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन ग्यारहवें महीने में प्रवेश कर गया है, उनकी मांगें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के वैधानिकीकरण से आगे बढ़ गई है।
- किसानों, खासकर पंजाब के किसानों ने मांग की है कि भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) से हट जाए और कृषि समझौते (AoA) के तहत सभी मुक्त व्यापार समझौतों को निलंबित कर दे। उनका तर्क है कि WTO के नियम विकसित देशों के पक्ष में हैं और AoA के कई खंड छोटे भारतीय किसानों के लिए हानिकारक है।
- उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में, पंजाब के किसानों ने 'WTO छोड़ो दिवस' मनाया था, जिसमें दावा किया गया था कि WTO की नीतियों से भारत की खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों और उनकी आजीविका, खासकर पंजाब में, को खतरा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

## किसान भारत से WTO से हटने की मांग क्यों कर रहे हैं?

- प्रदर्शनकारी किसानों के अनुसार, कृषि सब्सिडी को कम करने और निष्पक्ष व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए लागू किया गया WTO का कृषि पर समझौता (AoA) मूल रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के खिलाफ पक्षपाती है।
- उल्लेखनीय है कि AoA में कृषि उत्पाद शामिल हैं जबकि वानिकी, मत्स्य पालन और जूट और कॉयर जैसे रेशे शामिल नहीं हैं।
- AoA के ये नियम भारत के घरेलू समर्थन कार्यक्रमों जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अक्सर WTO की बैठकों में चुनौती दी जाती है।
- विकसित देशों के विपरीत, भारत विशेष सुरक्षा उपायों (SSG) की अनुपस्थिति के कारण आयात में उछाल के दौरान अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगा सकता है।
- इन मुद्दों को संबोधित करने में विफलता भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों, छोटे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकती है।

## विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता (AoA) क्या है?

- AoA विश्व व्यापार संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिस पर टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के 'उरुग्वे दौर' के दौरान बातचीत की गई थी।

- यह 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना के साथ लागू हुआ।
- इसमें कृषि उत्पादन और व्यापार के परिणामों के आधार पर "बॉक्स" द्वारा सब्सिडी का वर्गीकरण शामिल है:

  ➢ अम्बर (सबसे सीधे उत्पादन स्तरों से जुड़ा हुआ),

  ➢ ब्लू (उत्पादन-सीमित कार्यक्रम जो अभी भी व्यापार को विकृत करते हैं), और

  ➢ ग्रीन (न्यूनतम विकृति)।
- जबकि एम्बर बॉक्स में भुगतान कम किया जाना था, ग्रीन बॉक्स में भुगतान में कमी की प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई थी।

## पंजाब के किसान WTO को खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा क्यों मानते हैं?

- पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था गेहूं और धान पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें MSP प्रणाली के तहत सार्वजनिक खरीद राज्य के कृषि ढांचे की रीढ़ है। पंजाब की लगभग 90% रबी और खरीफ फसलें MSP के तहत खरीदी जाती हैं, जिसमें लगभग सभी चावल और 80% गेहूं केंद्रीय पूल में योगदान करते हैं।
- इस प्रकार सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित करने वाले WTO नियम उनकी आजीविका को खतरे में डालते हैं।

- उल्लेखनीय है कि छोटे किसान भारत की कृषि आबादी का 86% हिस्सा हैं और विशेष रूप से कमजोर हैं। उनके पास आधुनिक तकनीक, बाजार और वित्तपोषण तक पहुंच नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, WTO नियमों के तहत उदारीकृत वैश्विक व्यापार उन्हें अनुचित प्रतिस्पर्धा और सस्ते आयात के लिए उजागर करता है।
- यह बदले में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर सकता है और पारिस्थितिकी, आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

**एक विचारधारा देश में कृषि सहयोग की वर्तमान प्रणाली को दोषपूर्ण मानता है:**

- प्रो. अशोक गुलाटी जैसे विशेषज्ञ कृषि सहयोग की वर्तमान प्रणाली को दोषपूर्ण मानते हैं। इस संदर्भ में, OECD के उत्पादक समर्थन अनुमानों (PSE) को देखने की बात करते हैं। जो विभिन्न कृषि नीतियों, मुख्य रूप से बजटीय समर्थन और बाजार मूल्य समर्थन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक सामान्य पद्धतिगत ढांचा अपनाते हैं। इसके तुलनात्मक परिणाम भारत के कुछ नीति निर्माताओं को चौंका सकते हैं।
- 2023 को समाप्त होने वाली त्रैमासिक अवधि के लिए, OECD देशों ने अपने कृषि को सकल कृषि प्राप्तियों (PSE 13.8 प्रतिशत) के लगभग 14 प्रतिशत के बराबर

समर्थन दिया। चीन भी अपने कृषि को 14 प्रतिशत (PSE 14 प्रतिशत) के बराबर समर्थन देता है, जबकि भारत का PSE नकारात्मक (-) 15.5 प्रतिशत है।

- ऐसा निर्यात नियंत्रण, कीमतों को नीचे धकेलने के लिए घरेलू बाजार में डंपिंग, निजी व्यापार पर स्टॉकिंग सीमा लगाना, वायदा बाजारों पर प्रतिबंध लगाना आदि के परिणामस्वरूप नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन के कारण होता है।
- उल्लेखनीय है कि जब तक देश की कृषि नीतियां कृषि बाजारों को सही करने की कोशिश नहीं करतीं, तब तक भारतीय कृषि लंगड़ाती रहेगी और हमारे किसान उच्च और उच्च कीमतों के लिए आंदोलन करते रहेंगे।

# MCQ

1. चर्चा में रहे पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान द्वारा 'भारत को WTO से बाहर निकलने की मांग को लेकर दिए जाने वाले तर्कों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. WTO के कृषि समझौते में कृषि उत्पाद शामिल हैं जबकि वानिकी, मत्स्य पालन और जूट और कॉयर जैसे रेशे शामिल नहीं हैं।
   2. WTO के नियम भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   **Ans:(c)**

2. हाल में चर्चा में रहे कृषि उत्पादन और व्यापार से जुड़े अम्बर, ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स का उल्लेख निम्नलिखित किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा है?

(a) पेरिस संधि

(b) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

(c) बेसल समझौता

(d) कृषि पर समझौता (AoA)

**Ans:(d)**

3. चर्चा में रहे विश्व व्यापार संगठन का 'कृषि पर समझौता' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिस पर WTO के 'कानकुन दौर' के दौरान बातचीत की गई थी।
2. पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 'कृषि पर समझौता' को भारत जैसे विकासशील देशों के हानिकारक मानते है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans:(b)**

4. QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 रिपोर्ट द्वारा भारत की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति के बारे में कहे गए कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) भारत के स्नातक आवश्यक प्रासंगिक कौशल में बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूर्णतया तैयार हैं।

(b) भारत का 'कौशल फिट' स्कोर एशिया-प्रशांत के समकक्षों की तुलना में बेहतर है।

(c) भारत के नियोक्ता तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

**Ans:(c)**

5. चर्चा में रहे "QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025" के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत सभी संकेतकों में 25वें स्थान पर रहा, जिसमें कौशल और नियोक्ता की जरूरतों, शैक्षणिक तत्परता और आर्थिक परिवर्तन के बीच संरेखण भी शामिल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2. भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारियों के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**Ans:(a)**